आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)

रविवार 01.12.2024 समय 1830

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया, कहा– प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार कार्य कर रही है।
- खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल महाकुंभ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों को 1 लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की।
- प्रदेश में भू–कानून नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
- केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने एचआईवी संक्रमितों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील की।

राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ–2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सहयोग से प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार कार्य कर रही है। श्री धामी ने कहा कि राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सीधी भर्ती के पदों पर अन्य खिलाड़ियों की तरह चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही खेल महाकुंभ में जिला स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी स्पोर्ट्स किट प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल महाकुंभ विशिष्ट आयोजन है। इसमें खिलाड़ियों को ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक, जनपद होते हुए, राज्यस्तर तक प्रतिभा प्रदर्शन का मौका मिलता है।

खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल मंत्री ने कहा कि इस आयोजन से राज्य को बेहतर खिलाड़ी मिलने के साथ ही उत्तराखंड में खेलों के प्रति एक नया सामाजिक भाव भी बन रहा है।

श्रीमती आर्य ने कहा कि इस खेल महाकुंभ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ने वाले खिलाड़ी को 1 लाख रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा।

निकाय चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस वर्ष आयोग ने प्रत्याशियों की चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ ही सख्त नियम भी लागू कर दिए हैं। ये जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि अगर कोई प्रत्याशी चुनाव खर्च का ब्योरा प्रमाण के साथ नहीं देता है तो आयोग उस पर तीन साल का प्रतिबंध लगा देगा। इसके बाद वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

सर्वेक्षण परीक्षा

नैनीताल जिले में केन्द्र और राज्य सरकार के 135 शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में आगामी 4 दिसम्बर को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस सर्वेक्षण में कक्षा 3, 6 और 9वीं में अध्ययनरत छात्र प्रतिभाग करेंगे। परिक्षा को देखते हुए जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा के लिए जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिसका नम्बर 94 10 16 21 08 है।

भू कानून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में भू–कानून नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की जनता से उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए सरकार का सहयोग करने की अपील की।

प्रदेश में लंबे समय से नए भू–कानून की मांग हो रही है। जिसके बाद सरकार ने नए भू–कानून का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए उच्चाधिकारियों, तहसीलदार, विशेषज्ञों और अन्य लोगों के बीच मंथन चल रहा है।

विश्व एड्स दिवस

आज विश्व एड्स दिवस है। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के इंदौर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोगों से एचआईवी एड्स संक्रमित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और संक्रमित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील की है।

श्री नड्डा ने कहा कि केन्द्र सरकार ने एचआईवी सुरक्षा अधिनियम 2017 के माध्यम से संक्रमित व्यक्तियों के साथ किसी भी भेदभाव को रोकने का काम किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जांच और उपचार की नीति पर अमल किया। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप अब देश में एड्स से होने वाली मौत में 79 प्रतिशत की कमी आई है और नए संक्रमण भी 44 प्रतिशत कम हुए हैं।

बीएसएफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल– बीएसएफ को आज इसके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ का देश की रक्षा पंक्ति में महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने कहा कि यह बल साहस, समर्पण और असाधारण सेवा का प्रतीक है। श्री मोदी ने राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा में बीएसएफ की सतर्कता तथा साहस की सराहना की।

योग नीति

प्रदेश सरकार योग नीति के तहत योग प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है। आयुष विभाग के अपर सचिव डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार देना और उत्तराखंड को एक वैश्विक योग हब बनाना है। उन्होंने कहा कि नीति के तहत छोटे योग संस्थानों को सब्सिडी दी जाएगी और योग ग्रामों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन किया जाएगा। ये नीति केवल योग का प्रचार नहीं करेगी, बल्कि युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी।

सी०सी०टी०वी

सुरक्षा के दृष्टिगत नैनीताल छावनी परिषद की सी०सी०टी०वी से निगरानी रखी जा रही है। यह देश का पहला छावनी परिषद है, जो पूरी तरह से सी०सी०टी०वी से लैस है। क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल छावनी परिषद में स्थापित 180 सी०सी०टी०वी कैमरों के कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य असामाजिक तत्वों से छावनी परिषद क्षेत्र को सुरक्षित करना, सेना के जवानों और उनके परिवारों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना और महिलाओं, पर्यटकों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

और अब संक्षिप्त समाचार——

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने आज कोटद्वार में पांच दिवसीय प्राकृतिकविद प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और प्रशिक्षुओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा।

पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अजीत पाठक ने सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी से मुलाकात कर उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में लोक संपर्क और संचार की भूमिका पर चर्चा की।

चमोली जिले में बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद मास्टर प्लान के कार्यों में तेजी आ गई है। सरकार ने इस सीजन में बर्फबारी से पहले अधिकांश कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। आज जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मास्टर प्लान के तहत चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों और आगामी यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने आज विभिन्न न्यायालय में कार्यरत कोर्ट पैरोकारों की बैठक ली। उन्होंने सभी पैरोकारों के काज लिस्ट और पैरवी रजिस्टर चेक किए और कहा कि मुकदमों के पैरवी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी कोर्ट पैरोकारों को न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों में सभी गवाहों के समय से न्यायालय के समक्ष बयान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।